3 योग हमारी सनातन परंपरा का अभिन्न अंग है

5 राजनीति के कर्मठ और जुझारू राजनेता

7 चिंता का विषयः जलाशयों का घटता स्तर

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 07 प्रति सोमवार, 23 जून 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

नया प्रदेशाध्यक्ष न बनाने से पार्टी में पनप रही अंतर्कलह, टूटने लगे विरोधियों के सब्र के बांध

वीडी शर्मा को नहीं हटाया तो पार्टी को होगी मुश्किलें

पोस्टर-होर्डिंग में छोटी फोटो लगाने पर भी वीडी शर्मा को आपत्ति

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के कारण मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में सबकुछ ठीक नहीं चल पा रहा है। सत्ता और संगठन में वीडी शर्मा खटकने लगे हैं। नया प्रदेशाध्यक्ष न बनाने से पार्टी में अंतर्कलह पनपने लगी है। वहीं विरोधियों के सब्र का बांध भी अब टूटने लगा है। खासकर वह नेता जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदार हैं और काफी दिनों से इसकी लालसा रखे हुए हैं। यह नेता भले ही सार्वजनिक रूप से वीडी शर्मा का विरोध न कर पा रहे हों लेकिन अंदर ही अंदर वीडी शर्मा की कार्यशैली और अहंकार से परेशान हैं। पिछले कई महीनों से अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जायेगा। लेकिन यह केवल अटकलें मात्र बनकर रह जाती हैं।

15 फरवरी 2020 को वीडी शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। जिनका कार्यकाल बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। बावजूद इसके उनका कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा है। जिस कारण इस पद की रेस में आस लगाए बैठे नेता अंदर ही अंदर विरोध में हैं। निश्चित ही पार्टी हाईकमान की इस अनदेखी का खामियाजा पार्टी को 2028 के आम चुनावों में उठाना पड़ेगा।

क्या खुद को सबसे बड़ा मानने लगे हैं वीडी शर्मा?

संगठन हो या सत्ता, वीडी शर्मा खुद को सबसे बड़ा नेता मानने लगे हैं। जब ही तो पिछले दिनों भाजपा संगठन की एक बैठक में पोस्टर-होर्डिंग में छोटी फोटो लगाये जाने पर ऐतराज जता रहे थे। यहां उनका अहम जाग रहा था। उन्होंने साफ तो नहीं लेकिन इशारों ही इशारों में अन्य पदाधिकारियों और नेताओं को जता दिया कि वही प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं और पोस्टर-होर्डिंग में उनका ही फोटो बड़ा लगना चाहिए। यहां पर एक बात का जिक्र करना जरूरी है। भले ही इनके कार्यकाल में प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया हो,लेकिन वीडी शर्मा को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए की पार्टी का बेहतर प्रदर्शन उनके कारण हुआ है। (शेष पेज 2 पर)

प्रदेश के विकास और राज्य की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे निर्णय

छत्तीसगढ़ की जनता के हित में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिये जनकल्याणकारी फैसले

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ के लोक कल्याणकारी और सुशासन के प्रेरक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के अनुसुचित जाति समुदाय से आने वाले लोगों के लिये बड़ा निर्णय लिया है। जनता की खुशहाली और जीवन में नई रोशनी लाने के ध्येय वाक्य को लेकर कार्य कर रहे मुख्यमंत्री साय ने पिछले दिनों हुई राज्य की कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास और जनकल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव

तथा पबिया, पविया, पवीया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य एवं डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के समतुल्य छात्रवृत्ति देने की सहमति दी गई। वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत घर की छतों में सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना में राज्य शासन द्वारा उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता दिए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

बैठक में फैसला लिया गया कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने पर केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ-साथ राज्य की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। वर्ष 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 सोलर पावर प्लांट की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। (शेष पेज 2 पर)

नया प्रदेशाध्यक्ष न बनाने से पार्टी में पनप रही अंतर्कलह, टूटने लगे विरोधियों के सब्र के बांध

(पेज 1 का शेष)

बल्कि बीजेपी की लहर और नरेन्द्र मोदी-शिवराज सिंह चौहान-कैलाश विजयवर्गीय के चेहरे पर प्रदेश में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। वह तो केवल पार्टी के अध्यक्ष थे। सत्ता हासिल करने में उनका कोई रोल नही था। इस गलत फहमी से उनको जितनी जल्दी हो बाहर निकल आना चाहिए।

संगठन को खड़ा करने में नाकाम वीडी शर्मा

वीडी शर्मा की नाकामियों में एक इजाफा यह भी है की उन्होंने प्रदेश में संगठन को खड़ा करने में काफी कोताही बरती है ।अपने कार्यकाल में करीब 11 माह बाद तो उन्होंने जिला स्तर पर संगठन खड़ा किया था, जिससे जिला स्तर पर कई गुट तैयार हो गये। कह सकते हैं कि उन्होंने संगठन के कार्य में कोई दिलचस्पी नही दिखाई बल्कि अपनी नेतागीरी जमाने में लगे रहें ।आज भी वह खुद के अलावा किसी को तवज्जो ही नही देते हैं। हाल ही में प्रदेश स्तर पर संगठन के पद भरे गये हैं उसमें भी काफी विरोधाभास देखने में मिला है। वीडी शर्मा ने अपने चहेतों को ही इन पदों पर बिठाया है। यहां तक सत्ता के लोगों की पसंद को भी तवज्जो नही दी गई।

भूपेंद्र सिंह की तीखी प्रतिक्रिया से समझें अंतर्कलह

बीजेपी में समय-समय पर कलह की खबरें सामने आती रही हैं और अब एक बार फिर ऐसा ही कुछ होता दिख रहा है। पार्टी के अंदरुनी विवादों में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम सामने आ रहा है। यह मामला दिसम्बर 2024 का है। जब पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने एक मंत्री और प्रदेशाध्यक्ष को कठघरे में खड़ा कर दिया था। उस समय भूपेन्द्र सिंह ने कहा था कि एक मंत्री जानबूझकर पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह ने कहा, 'वीडी शर्मा को पार्टी में आए हुए 5 से 7 साल हुए हैं। वे इससे पहले ABVP में काम करते थे।' वीडी शर्मा ने अपने पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा।

क्या वीडी शर्मा को मिल रहा सामान्य वर्ग का फायदा?

वीडी शर्मा सामान्य वर्ग से आते हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं। शायद पार्टी जातियों के समीकरण को बिठाने के कारण ही वीडी शर्मा को अभी तक ढो रही हो। ऐसा इसलिए माना जा सकता है क्योंकि प्रदेश में सामान्य वर्ग का बहुत बड़ा तबका है। जो सत्ता और संगठन में भी अपना प्रभाव रखता है। जाति के संतुलन को बनाये रखने के कारण भी अभी तक नये प्रदेश अध्यक्ष पर फैसला नहीं हो पा रहा है ।बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जातिगत समीकरण का पूरा ध्यान रखा है। ओबीसी वर्ग से सीएम बनाया तो डिप्टी सीएम आदिवासी और सामान्य वर्ग का दिया।

05 साल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की संपत्ति में आया उछाल

वीडी शर्मा की बीते 05 साल में संपत्ति 04 गुना से ज्यादा बढ़ी है। वीडी शर्मा लखपति से करोड़पति हो गए। 05 साल पहले वीडी शर्मा की संपत्ति करीब 68 लाख और पत्नी की कुल चल-अचल संपत्ति को मिलकर करीबन 01 करोड़ रुपए थी, जिसमें अब 04 गुना से ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है। वीडी शर्मा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने नामांकन के साथ संपत्ति का ब्यौरा पेश किया था। उस समय वीडी शर्मा की नगदी, बैंक बैलेंस सहित कुल चल संपत्ति 21 लाख 37 हजार 581 रुपए और पत्नी स्तुति शर्मा की 17 लाख 49 हजार 240 रुपए बताई थी। साल 2024 में शपथ पत्र के अनुसार वीडी शर्मा की संपत्ति शपथ पत्र में नगदी, बैंक बैलेंस सहित अपनी कुल चल संपत्ति 1 करोड़ 44 लाख 41 हजार 16 रुपए, जबकि पत्नी स्तुति शर्मा की 32 लाख 15 हजार 621 रुपए बताई है। शपथ पत्र में अपनी कुल अचल संपत्ति करीबन 03 करोड़ की बताई है। वीडी शर्मा अब एक वेयरहाउस के मालिक हैं। यह वेयरहाउस उन्होंने जबलपुर के पाटन में 71 हजार स्क्वायर फीट जमीन लीज पर लेकर बनवाया है। इसके अलावा मुरैना में अलग-अलग स्थानों पर 0.840 एकड़, 0.012 एकड़, 0.042 एकड़, 1.43 एकड़, 0.462 एकड़ और 0.660 एकड़ भूमि है। भोपाल के दानिश हिल्स में डुप्लेक्स भी है। वीडी शर्मा की पत्नी स्तुति शर्मा ने जून 2021 को 1.71 हेक्टेयर भूमि पाटन, जबलपुर को खरीदी। उनके पास जबलपुर में एक मकान भी है।

निश्चित ही अब समय आ गया है कि पार्टी हाईकमान जल्द से जल्द प्रदेश में अध्यक्ष का चेहरा बदले। नहीं तो बहुत देर हो जायेगी। क्योंकि पार्टी के अंदर और संगठन के अंदर वीडी शर्मा का काफी विरोध होने लगा है। अंदर ही अंदर कई नेताओं ने गुट पनपने लगे हैं जो आने वाले समय में नुकसान दायक साबित होंगे।

छत्तीसगढ़ की जनता के हित में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिये जनकल्याणकारी फैसले

(पेज 1 का शेष)

इससे वित्तीय वर्ष 2025-26 में 180 करोड़ एवं 2026-27 में 210 करोड़ रूपए का वित्तीय भार आएगा। इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी होगी और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार इसे लागू करेगी। कंपनी इस योजना के संचालन के लिए एक अलग बैंक खाता खोलेगी, जिसमें सब्सिडी की राशि रखी जाएगी और उसका हिसाब-किताब किया जाएगा।

राज्य में होगा टाइगर फाउंडेशन सोसायटी का गठन

छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी का गठन करने का निर्णय लिया है। यह सोसायटी वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत काम करेगी। यह सोसायटी बाघों और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में सीधे शामिल होगी। यह स्थानीय समुदाय की भागीदारी से ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देगी।

आदिवासी महिलाओं को रोजगार के अवसर

ब्रांड हस्तांतरण से एग्रो व फूड

प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय कच्चे माल की मांग बढ़ेगी और आदिवासी महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। ट्रेडमार्क हस्तांतरण से राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस सेवकों के प्रकरण में उनके परिवार के किसी भी पात्र सदस्य (महिला या पुरूष) को विकल्प के आधार पर पुलिस विभाग के अलावा, किसी अन्य विभाग में, राज्य के किसी भी जिला, संभाग में अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकेगी। वहीं स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (एसएमईटी) के गठन की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ में स्टेट मिनिरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के तहत समस्त गौण खनिजों से प्राप्त होने वाली रायल्टी 02 प्रतिशत राशि अतिरिक्त रूप से एसएमईटी फंड में जमा की जाएगी।

ई-वे बिल की सीमा में वृद्धि

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के भीतर माल परिवहन के लिए अनिवार्य ई-वे बिल की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 01 लाख कर दी है। यह निर्णय विशेष रूप से छोटे व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। इस निर्णय से व्यापारियों को 01 लाख तक के मूल्य के सामानों के परिवहन में अब ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होगी। इस निर्णय से राज्य में ई-वे बिल जनरेट करने वाले लगभग 26% व्यापारियों को ई-वे बिल जनरेट करने से मुक्ति मिलेगी। इस निर्णय से ई-वे बिल जनरेशन में 54 प्रतिशत की कमी आएगी, जिससे अनुपालन व्यय में उल्लेखनीय कमी आएगी। हालांकि, कुछ विशेष वस्तुएं जैसे पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, विशिष्ट लकड़ी उत्पाद जैसे– प्लायवुड, लेमिनेटेड शीट, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड, आयरन, स्टील एवं उसके सामान, कोयला के लिए यह छूट लागू नहीं होगी। व्यापारियों द्वारा लंबे समय से ई-वे बिल में छूट दिए जाने की मांग पर यह निर्णय लिया गया है, जो व्यापार को सुगम और लागत प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है।

योग कोई नई पद्धति नहीं, बल्कि हमारी प्राचीन सनातन परंपरा का अभिन्न अंग है: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि योग कोई नई पद्धति नहीं, बल्कि हमारी प्राचीन सनातन परंपरा का अभिन्न अंग है, जिसे ऋषि-मुनियों ने विकसित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप 2015 से प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जा रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आज 175 से अधिक देशों में योग की गूंज सुनाई देती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिला मुख्यालय में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया और सभी को शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री के साथ जनप्रतिनिधियों, स्कूली छात्र-छात्राओं, अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास में भाग लिया। योग प्रशिक्षकों ने चक्रासन, अर्धचक्रासन, कपालभाति, अनुलोम-विलोम, प्राणायाम, वज्रासन सहित विभिन्न आसनों का अभ्यास कराया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि दिन के 24 घंटों में से कुछ समय योग के लिए

अवश्य निकालें। इससे न केवल गंभीर बीमारियां दूर होती हैं, बल्कि भविष्य में रोग होने की संभावना भी कम होती है। उन्होंने जेनेरिक दवाओं के उपयोग पर बल देते हुए कहा कि ये दवाएं प्रभावी, सुलभ और किफायती हैं। मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों की बड़ी संख्या में भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि योग से बच्चों का मन शांत होता है और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित होता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नालंदा परिसर का भूमिपूजन किया। 11.29 करोड़ रुपये की लागत से 2 एकड़ में बनने वाले इस परिसर में 500 विद्यार्थी एक साथ अध्ययन कर सकेंगे। परिसर में एक आकर्षक उद्यान भी विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा। आज ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र भी जागरूक होकर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार ने सभी जिला मुख्यालयों और बड़े शहरों में नालंदा परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कुल 107.81 करोड़ रुपये के 64 कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। इसमें जशपुर विधानसभा क्षेत्र में 61.20 करोड़ रुपये के 85 कार्यों का भूमिपूजन और 15.80 करोड़ रुपये के 6 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इसी प्रकार, कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के फरसाबहार विकासखंड में 24.90 करोड़ रुपये के 15 कार्यों का भूमिपूजन और 5.91 करोड़ रुपये के 4 कार्यों का लोकार्पण किया गया।

योग आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा ने कहा कि जशपुर की वादियां अत्यंत सुंदर हैं और योग के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती हैं। यहां की चाय, काजू और नाशपाती जैसी फसलें इसे और विशेष बनाती हैं। उन्होंने कहा कि योग कोई पाठ्यक्रम नहीं, बल्कि जीवन जीने की शैली है, जिसे निरंतर अभ्यास से आत्मसात किया जा सकता है। कलेक्टर रोहित व्यास ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। स्वागत भाषण समाज कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती रोकिमा यादव ने दिया। इस अवसर पर पूर्व सांसद रणविजय सिंह जूदेव, पद्मश्री जागेश्वर राम यादव, जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, माटीकला बोर्ड अध्यक्ष शंभूनाथ चक्रवर्ती, सनिर्माण कर्मकार मंडल अध्यक्ष श्री रामप्रताप सिंह उपस्थित थे।

कच्चे घरों से निजात, पीएम जनमन योजना से मिले पक्के मकान

-संवाददाता

जगत प्रवाह. रायगढ़। जिले के धरमजयगढ़ के सुदूर वनांचल में बसे जबगा गांव में पीएम जनमन योजना से उन परिवारों के लिए एक साथ एक कालोनी के रूप में बसाए गए हैं। बिरहोर परिवार अब अपने पुराने कच्चे मिट्टी के घर को छोड़कर अपने पक्के प्रधानमंत्री आवास में रह रहे हैं। पक्का घर से मिलने से अब उन्हें सुरक्षा और स्थिरता का अहसास हो रहा है, जिससे उनके चेहरे पर स्पष्ट खुशी दिखाई दे रही हैं। यहां पर निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति- बिरहोर के 07 परिवार निवासरत हैं। जो कि 2016 के पूर्व जंगल में ही बने एक गुफा में निवास करते थे।

बलपेदा के ग्रामीणों ने उन्हें ग्राम के निकट आबादी प्लॉट में निवास करने के लिए कह कर जंगल से बाहर लाये थे। वहीं इनके द्वारा रहने के लिए झोपड़ी एवं कच्चे मकान बनाये गये थे, पक्का आवास तो जैसे इनके लिए सपना था। जंगल में प्राप्त होने वाले महुल पेड़ से पालतु जानवरों जैसे- गाय, बकरी को बांधने वाली रस्सी बनाकर एवं स्थानीय भाषा में बोले जाने वाले बगाई नामक घास जिससे रस्सी बनाकर खाट का नेवार बनाया जाता है, जिसे बेचकर अपने कमाए पैसों से दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते है। इन्हीं कमाएं हुए पैसों से अपने परिवार के सदस्यों का भरण पोषण भी करते है। यह भोजन के रूप में कोदो, कनकी जैसे अनाज को ग्रहण करते हैं। गांव पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण हर साल तेज हवा, पानी के कारण घरों को बहुत नुकसान होता था।

जिसके कारण इन परिवारों को हर साल घर की मरम्मत करनी पड़ती है। इस वजह से इन परिवारों की आय का अधिकांश हिस्सा घर मरम्मत में ही खर्च हो जाता था। जिससे इन परिवारों के आशियाने की चिंता बनी रहती थी। बरसात के दिनों में कच्चे मकानों में साफ-सफाई की कमी से बीमारी का खतरा भी बना रहता था। पक्के मकान मिलने के बाद ये सारी चिंता और चुनौतियां अब दूर हो गई हैं। पक्के मकानों के इन परिवारों को सुरक्षा और स्थिरता प्रदान की है, जिससे उनमें काफी खुशी है। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अपना धन्यवाद ज्ञापित किया है।

शोभा यात्रा का कांग्रेस ने किया स्वागत

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। सकल जैन समाज द्वारा आयोजित पंच कल्याणक महोत्सव के अंतिम दिन विशाल शोभा यात्रा निकली गई जो शहर के मुख्य मार्ग से निकली शोभा यात्रा का जगह सर्व समाज एवं राजनैतिक संगठनों ने भी स्वागत किया। हरदा रोड फॉरेस्ट नाके के पास नगर कांग्रेस द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया तथा शीतल जल वितरित किया। शोभा यात्रा में शामिल संत पूज्य निर्णय सागर जी महाराज के पद प्रक्षा लन नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष जायसवाल एवं साथियों ने किया तथा आशीर्वाद प्राप्त किया। शोभा यात्रा में शामिल जैन समाज के धर्मावलंबियों का मोती की माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर दिनेश विश्वकर्मा, मनवीर रघुवंशी, राजेश नाथ, जितेंद्र सोनकिया, शिवम कनौजिया, बृज सोनाकिया, अतुल टांक, लालू शुक्ला, राकेश काशीव, अर्पित अग्रवाल, जयेंद्र पटेल, पप्पा लाल,गिरीश घुरे, ऋतु सोलंकी, हीरा घुरे, मधु जायसवाल, सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे

जमीन पर कब्जा करने को लेकर बुजुर्ग महिला ने दिया थाने में आवेदन

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरीखला। मामला देवरी के ग्राम पंचायत तीतरपानी से जुड़ा है। जहां एक पारिवारिक विवाद के चलते भाजपा के एक दबंग द्वारा जमीन पर कब्जा करने की कोशिश बार-बार की जा रही और जिनके नाम वह जमीन है उनको खेत पर न जाने की धमकी भी दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक श्रीमति कुसुम दुबे जिनकी उम्र 78 वर्ष है, ने थाना महाराजपुर में एक शिकायती आवेदन देकर आरोप लगाया है कि तीतरपानी निवासी जितेन्द्र पटैरिया उर्फ पप्पू पटैरिया के द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा करने की बार-बार कोशिश की जा रही है एवं बोवनी नहीं करने दे रहे और जितेन्द्र पटैरिया ने धमकी दी है कि यदि इस खेत पर दोबारा आई तो ठीक नही होगा। कुसुमरानी के पुत्र शैलेन्द्र ने बताया है कि जैसे ही खरीफ फसल की बोवनी करने गये तो उन्होने मां के साथ धक्का मुक्की की एवं जान से मारने की धमकी दी है। पुत्र ने बताया कि जितेन्द्र पटैरिया द्वारा यहां के विधायक बृजबिहारी पटैरिया की भी धमकी देते हैं और कहते हैं आप कहीं भी चले जाओ मेरा कोई कुछ नही कर सकता। गौरतलब है कि जितेन्द्र पटैरिया एक भाजपा के बडे नेता हैं जिनके यहां सांसद, विधायकों का आना जाना लगा रहता है। जिस कारण कार्यवाही नही हो रही।

सम्पादकीय

देश की राजनीति में क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान

देश के प्राचीन एवं संविधान सम्मत नाम 'भारत' का जिस प्रकार विरोध किया जा रहा है, उससे दो बातें सिद्ध हो जाती हैं। पहली, देश में अभी भी एक वर्ग ऐसा है, जो मानसिक रूप से औपनिवेशिक गुलामी का शिकार है। भारत के 'स्व' और उसकी सांस्कृतिक परंपरा को लेकर उसके मन में गौरव की कोई अनुभूति नहीं है। दूसरी, वास्तव में यह समूह 'भारत विरोधी' है। जब भी भारतीयता का प्रश्न आता है, तो यह समूह उसके विरुद्ध ही खड़ा मिलता है। एक तरह से यह उसका स्वभाव बन गया है। देश की जनता देखकर आश्चर्यचकित है कि 'भारत' का विरोध करने के लिए राजनीतिक दल एवं वैचारिक समूह किस स्तर पर पहुँच गए हैं। 'भारत' को 'भारत' कहने पर आखिर हाय-तौबा क्यों मची हुई है? भारत विरोधी समूह को एक बार संविधान सभा की बहस पढ़नी चाहिए। निश्चित ही उसे ध्यान आएगा कि तत्कालीन कांग्रेसी नेता अपने देश का नाम 'भारत' ही रखना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजी मानसिकता के दास लोगों के सामने उनकी चली नहीं। आखिरकार 'भारत' के साथ 'इंडिया' नाम भी चिपक गया।

कांग्रेस के वरिष्ठ एवं सम्मानित नेता सेठ गोविंद दास ने कहा था कि वेदों, महाभारत, पुराणों और चीनी यात्री ह्वेन-सांग के लेखों में 'भारत' देश का मूल नाम था। इसलिए स्वतंत्रता के बाद संविधान में 'इंडिया' को प्राथमिक नाम के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए। वास्तव में भारत हमारी संस्कृति एवं परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इंडिया शब्द के साथ ऐसी कोई गौरव की अनुभूति कराने वाली बात नहीं जुड़ी है। भारत कहने पर, हमें समृद्धशाली परंपरा का स्मरण होता है। स्वाभाविक ही हम लोग अपनी परंपरा से जुड़ जाते हैं। जब भी किसी ने अपने देश को भावनात्मक आधार पर स्मरण किया है, उसने उसके लिए भारत शब्द ही उपयोग किया है। राष्ट्रगान में 'इंडिया भाग्य विधाता' नहीं आता, अपितु 'भारत भाग्य विधाता' गाया जाता है।

स्वतंत्रता के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों ने भी 'भारत माता की जय' का नारा बुलंद किया। संविधान सभा में जब भारत के नाम को लेकर आए प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, तब प्रसिद्ध गांधीवादी नेता एवं कांग्रेस सरकार के मंत्री महावीर त्यागी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की दलीलों पर व्यंग्य करते हुए कहा कि "यह (नेहरू जी) हैरो (विलायत) में पढ़े हैं और मैंने केवल एक छोटी-सी पाठशाला में अंग्रेजी पढ़ी है। पर मेरे गुरु नंदराम जी ने छठी क्लास में मुझे बताया था कि व्याकरण के अनुसार 'प्रोपर नाउन' (व्यक्तिवाचक संज्ञा) का अनुवाद नहीं होता है, पर जब हैरो की ग्रामर के विद्यार्थी कहते हैं कि नामों का अनुवाद भी हो सकता है, तो मैं अपना संशोधन वापस लेता हूँ। पर मेरे प्रतिष्ठित मित्र को सचेत रहना चाहिए कि कल के अंग्रेजी समाचार पत्रों में यह छप सकता है कि ऑनरेबिल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर 'जैमरैड कैनालू' के कहने पर त्यागी ने अपना संशोधन वापस लिया"। नेहरू जी ने जब पूछा कि क्या कहा तुमने? तब वाकपटुता के लिए प्रसिद्ध महावीर त्यागी ने कहा – जैम का अर्थ है जवाहर, रैड का लाल और कैनालू का अर्थ है नेहरू। दरअसल, महावीर त्यागी ने 'इंडिया दैटिज भारत' प्रस्ताव में एक ऐसी गलती की ओर ध्यान आकर्षित किया था, यदि उसे नहीं सुधारा जाता तो आज संविधान की दुहाई देने वाले लोग कहते कि अपने देश का नाम न तो इंडिया है और न ही भारत, संविधान के अनुच्छेद-1 के अनुसार हमारे देश का नाम 'इंडिया दैटिज भारत' है। बहरहाल, विश्व में शायद ही किसी देश का ऐसा उदाहरण नहीं मिले, जिसका उसकी अपनी भाषा में नाम अलग हो और अंग्रेजी में अलग। सबका एक ही नाम चलता है। दुनिया भर में अनेक उदाहरण हैं, जब देशों ने बाह्य पहचान को हटाकर अपने 'स्व' का धारण किया और अपना वास्तविक नाम स्वीकार किया है।

सियासी गहमागहमी

चिटनिस और आर्यः किसे मिलेगा ताज?

मध्यप्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर लंबे समय से प्रतीक्षा चल रही है। चुनाव हुए लगभग तीन महीने का समय पूरा हो गया है लेकिन अभी तक फिलहाल नये प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा नहीं हो सकी है। दो दिन पूर्व पूर्वमंत्री अर्चना चिटनिस और लाल सिंह आर्य के लगातार हो रहे दिल्ली दौरे से कयास लगाना शुरू हो गया है कि इन्हीं दोनों में से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष का दावेदार बनाया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भाजपा प्रयोगधर्मी पार्टी है। जिस तरह से उन्होंने पहली बार विधायक का चुनाव जीते राजस्थान में भजनलाल सिंह को मुख्यमंत्री का दायित्व दिया उसी तरह दिल्ली की कमान महिला नेतृत्व में के हाथ में सौंपकर उन्होंने महिला सशक्तिकरण का प्रमाण दिया है। ऐसे में कयास लगाये जा रहे हैं कि जल्द ही प्रदेश में नये प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चिटनिस या आर्या को जिम्मेदारी मिल सकती है।

कम नहीं हो रही बघेल की मुश्किलें

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के भ्रष्ट नेता भूपेश बघेल की परेशानी बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल कुछ महीने पहले जिन स्थानों पर सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की थी उन स्थानों से अब कई महत्वपूर्ण सबूत प्राप्त हुए हैं। यह सबूत इस बात का इशारा करता है कि अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में मुख्यमंत्री बघेल ने अरबों रुपये के घोटालों को अंजाम दिया है। इसका पूरा ब्यौरा सीबीआई को बघेल की करीबी रही महिला अफसर सौम्या चौरसिया के घर से प्राप्त हुए हैं। कुल मिलाकर सीबीआई जैसे-जैसे इस पूरे मामले की परते खोलेगी, वैसे-वैसे बघेल और चौरसिया की मुश्किलें बढ़ती जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि बघेल इस पूरी कार्रवाई से कैसे खुद को बचा पाते हैं।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

वोटर लिस्ट? Machine-readable फॉर्मेट नहीं देंगे।
CCTV फुटेज? कानून बदलकर छिपा दी।
चुनाव की फोटो-वीडियो? अब 1 साल नहीं, 45 दिनों में ही मिटा देंगे। जिससे जवाब चाहिए था - वही सबूत मिटा रहा है।
साफ दिख रहा है - मैच फिक्स है। और फिक्स किया गया चुनाव, लोकतंत्र के लिए जहर है।

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

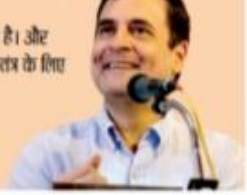

छतरपुर में एक महिला और उसके दो बच्चों का दिनदहाड़े अपहरण हो गया। एक युवक अपने साथियों के साथ पहुंचा और फायरिंग करते हुए महिला और उसके 7 वर्षीय बेटे और 5 वर्षीय बेटी को जबरन कार में बैठाकर ले गया।
यह घटना बताती है कि मध्य प्रदेश में जंगल राज आ चुका है।

-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

दक्षिण भारत की राजनीति के कर्मठ और जुझारू राजनेता हैं एमके स्टालिन

समता पाठक/जगत प्रवाह

एम. के. स्टालिन तमिलनाडु के दिग्गज नेताओं में से एक हैं। स्टालिन का जन्म 1 मार्च 1953 को तमिलनाडु के प्रमुख द्रविड़ नेता और तमिलनाडु के पांच बार के मुख्यमंत्री, कलैगनर एम. करुणानिधि और उनकी दूसरी पत्नी दयालु अम्मल के घर तमिलनाडु में हुआ। स्टालिन को करुणानिधि के उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया गया। एम. के. स्टालिन द्रमुक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। शहर में सड़क यातायात की भीड़ को कम करने के लिए उन्होंने 94.5 करोड़ रुपये की कुल लागत पर नौ फ्लाईओवर और 4.92 करोड़ रुपये की कुल लागत पर उननचास छोटे पुलों का निर्माण किया। उन्होंने जापान की वित्तीय मदद से होगेनक्कल जल योजना को सफलतापूर्वक संभाला। 1967 में अपनी पार्टी डीएमके के लिए चुनाव प्रचार किया।1967 में एमके स्टालिन का राजनीतिक करियर 14 साल की उम्र में शुरू हुआ। 1973 में वे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की जनरल कमेटी के लिए चुने गए। 1976 में उन्हें आपातकाल के दौरान मीसा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया और पुलिस द्वारा क्रूर व्यवहार किया गया। 1984 में उन्हें पार्टी की युवा शाखा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने थाउजेंड लाइट्स निर्वाचन क्षेत्र, चेन्नई से विधानसभा चुनाव लड़ा और हार गए। 1989 में उन्हें थाउजेंड लाइट्स निर्वाचन क्षेत्र, चेन्नई के विधायक के रूप में चुना गया। उन्होंने अन्नाद्रमुक की थेंबीदुरई के खिलाफ बड़े अंतर से जीत दर्ज की और तमिलनाडु विधानसभा में अपनी शुरुआत की। 1991 में थाउजेंड लाइट्स निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधानसभा चुनाव में हार गए। 1996 में उन्हें फिर से थाउजेंड लाइट्स निर्वाचन क्षेत्र, चेन्नई के विधायक के रूप में चुना गया।1996 में उन्हें चेन्नई के मेयर के रूप में चुना गया। वे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित शहर के पहले मेयर बने। 2001 में वे तीसरी बार हजार लाइट्स निर्वाचन क्षेत्र, चेन्नई के विधायक चुने गए। 2001 में वे लगातार दूसरी बार चेन्नई के मेयर चुने गए। 2003 में उन्हें पार्टी के जनरल काउंसिल द्वारा अपनी पार्टी द्रमुक के उप महासचिव के रूप में चुना गया था। 2006 में चौथी बार, वे चेन्नई के थाउजेंड लाइट्स निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए। वे राज्य के नगरपालिका प्रशासन और ग्रामीण विकास मंत्री बने। 2008 में उन्हें पार्टी की सामान्य परिषद द्वारा द्रमुक के कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। 2009 में उन्हें राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में पदोन्नत किया गया। वे तमिलनाडु के पहले उपमुख्यमंत्री बने। 2011 में अपने पिछले निर्वाचन क्षेत्र थाउजेंड लाइट्स से लगातार चार बार जीत के बावजूद, वे इस बार चेन्नई के कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र में चले गए और वहाँ से विधायक चुने गए। 2016 में उन्हें एक बार फिर चेन्नई के कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में चुना गया, जहां वे तमिलनाडु विधानसभा के इतिहास में सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले तमिलनाडु विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बने। 2017 में उन्हें पार्टी के जनरल काउंसिल द्वारा अपनी पार्टी, द्रमुक के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 2018 में पार्टी के अध्यक्ष कलइगनर एम करुणानिधि के निधन के बाद पार्टी की जनरल काउंसिल द्वारा स्टालिन को द्रमुक पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। 2021में द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन कोलथुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधान सभा पहुंचे और 07 मई 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

घरेलू हिंसा का घेरा

-विजय गर्ग

महिलाओं के लिए उनका घर-आंगन सबसे सुरक्षित स्थान होना चाहिए। परिवार और परिवेश में अपनों का संबल मिलना चाहिए। मान-सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। दुखद है कि भारत ही नहीं, कमोबेश हर देश में घरेलू हिंसा का दंश महिलाओं के हिस्से है। मन और मान को ठेस पहुंचाने वाले इस बर्ताव के रंग-ढंग भले अलग हों, वैश्विक स्तर पर महिलाएं इस पीड़ा को झेल रही हैं। व्यक्तित्व और अस्तित्व को चोट पहुंचाने वाली घरेलू हिंसा महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए भी चिंता का विषय बनी हुई है। अपनी ही देहरी के भीतर स्त्रियों के साथ होने वाला हिंसात्मक व्यवहार मानवाधिकार का भी एक संवेदनशील मुद्दा है। हमारे देश में महिलाओं की बड़ी आबादी घरेलू हिंसा झेलने को विवश है। प्रगतिशील सोच और परिवर्तन की बहुत-सी बातों के बीच मानवीय व्यवहार के इस मोर्चे पर आज भी बदलाव की प्रतीक्षा है। यही कारण है कि घरेलू हिंसा की रोकथाम और पीड़ित स्त्रियों की सुरक्षा सहयोग से जुड़े विषयों की सामाजिक पारिवारिक परिवेश में ही नहीं, न्यायिक निर्णयों में भी चर्चा होती रहती है।

आज भी बड़ी संख्या में महिलाएं घर के भीतर दुर्व्यवहार और मारपीट का शिकार बनती हैं। तकनीकी तरक्की और शिक्षा के बढ़ते आंकड़ों के बावजूद इस मामले में जागरूकता की कमी भी स्पष्ट दिखती है। सजग-शिक्षित महिलाएं भी अपना परिवार बचाने के लिए इस दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं करतीं। इसीलिए घरेलू हिंसा से स्त्रियों की सुरक्षा पुख्ता करने जुड़े इस पहलू पर उच्चतम न्यायालय ने सहयोगी और सजग परिवेश बनाने की बात कही। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता लाने, अधिनियम के तहत सेवाओं के प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने और इसके प्रावधानों का मीडिया में पर्याप्त प्रचार करने और व्यापक कदम उठाने चाहिए। विशेषकर घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत निशुल्क कानूनी सहायता और सलाह के अधिकार के बारे में महिलाओं के बीच जागरूकता फैलानी चाहिए। इन निर्देशों में शीर्ष अदालत ने यह भी जोड़ा कि अगर कोई महिला कानूनी सहायता या सलाह के लिए संपर्क करती है, तो उसे शीघ्रता से सहायता प्रदान की जाए, क्योंकि अधिनियम प्रत्येक महिला को निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार की गारंटी देता है।

हमारे परिवारों में अधिकतर बदलाव सतही स्तर पर ही हुए हैं। मानसिकता और व्यवहार के मोर्चे पर सार्थक परिवर्तन अब तक नहीं आया। ऐसे में जागरूकता की कमी और पारिवारिक दबाव घरेलू हिंसा का घेरा कसे हुए है। पिछले वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं के खिलाफ अपराधों की 25,743 शिकायतें मिलीं थी। इनमें सबसे अधिक 6,237 शिकायतें घरेलू हिंसा की थीं। यानी आपराधिक आंकड़ों में 24 फीसद की हिस्सेदारी घरेलू हिंसा की रही। यही वजह है कि इन शिकायतों में 'सम्मान के साथ जीने के अधिकार' की मांग वाली शिकायतें अधिक थीं, जो कुल शिकायतों का लगभग 28 फीसद हैं। इतना ही नहीं, दहेज उत्पीड़न के मामले भी 17 फीसद रहे। समझना कठिन नहीं है कि दहेज उत्पीड़न के मामलों में भी शुरुआत में ही कई महिलाएं शारीरिक-मानसिक हिंसा झेलती ही हैं।

दुखद है कि शिक्षित समाज में भी रुग्ण मानसिकता वाला यह व्यवहार महिलाओं के हिस्से है। घरेलू हिंसा का दंश भी हर समुदाय और हर वर्ग में देखने को मिलता है। अपने ही घर में महिलाओं के साथ हिंसक व्यवहार करने वाले शिक्षित और अशिक्षित, हर तबके के लोग हैं। भ्रम यह भी है कि केवल घरेलू महिलाएं ऐसी हिंसा और अपमान झेलती हैं। कई कामकाजी और आत्मनिर्भर स्त्रियां भी घरेलू हिंसा झेलती हैं, क्योंकि यह बर्ताव असल में नकारात्मक और अमानवीय सोच से जुड़ा है, जिसमें परिवर्तन लाना दुष्कर कार्य बना हुआ है। स्त्रियों के मान को ठेस पहुंचाने वाली सोच में बदलाव की धीमी गति को हाल ही में आए आंकड़े भी पुख्ता करते हैं। वर्ष 2025 की पहली तिमाही में राष्ट्रीय महिला आयोग में अब तक 7,698 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। शिकायतों की इस सूची में भी सबसे अधिक मामले घरेलू हिंसा के ही हैं। पीड़ादायक यह है कि महानगरों से लेकर गांवों-कस्बों तक, आंकड़ों में ही नहीं सहज रूप से भी सामाजिक परिवेश में इस विद्रूप व्यवहार की झलक दिख जाती है।

घरेलू हिंसा का सबसे दुखद पक्ष यह कि इसे महिला की व्यक्तिगत समस्या समझा जाता है। आमतौर पर स्वजन भी यह दंश झेलती स्त्रियों का साथ नहीं देते। परिजन चुपचाप सब कुछ सहने की नसीहत देने लगते हैं। वहीं कानूनी मोर्चे पर भी स्थितियां सहज नहीं हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि हाल के वर्षों में सामने आए घरेलू हिंसा के झूठे आरोपों ने सचमुच इस दुर्व्यवहार की शिकार बन रहीं महिलाओं को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। अधिकतर महिलाएं शिकायत दर्ज कराने के बजाय चुप्पी चुन लेती हैं। एक रपट के अनुसार हमारे देश में केवल 0.1 फीसद महिलाएं ऐसी हिंसा के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए आगे आती हैं। बुनियादी रूप से देखा जाए तो यह स्त्री-पुरुष के भेद से परे हर मनुष्य के आत्मसम्मान का मोल समझने का विषय है।

समझना आवश्यक है कि घर के भीतर होने वाली इस शारीरिक और मानसिक हिंसा के पीछे लैंगिक विभेद की सोच एक अहम कारण है। भेदभाव भरी इसी सोच के चलते कई कामकाजी महिलाओं की उपलब्धियां भी इस दुर्व्यवहार का कारण बन जाती हैं। आज भी जीवन साथी की रूढ़िवादी सोच के चलते न तो स्त्रियों की योग्यता की सहज स्वीकार्यता दिखती है और न ही पारिवारिक स्तर पर पराए घर से आई बेटी के प्रति मान भरा व्यवहार। ऐसी हिंसा को बहुत से परिवारों में समर्थन भी मिलता है। नतीजतन, घरेलू हिंसा झेल रहीं स्त्रियां अक्सर अकेली पड़ जाती हैं। ऐसे में अपनों की सोच और बर्ताव का बदलना ही घरेलू परिस्थितियों को बदल सकता है, ताकि सम्मानजनक और सुरक्षित व्यवहार स्त्रियों के हिस्से आए। अंतरिक्ष तक पहुंच बनाने के दौर में बहुत आवश्यक है कि महिलाओं के लिए अपना आंगन सुरक्षित हो।

अमेरिकी वर्चस्ववाद के शिकार डोनाल्ड ट्रंप

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

इजरायल के कंधे पर बंदूक रखकर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी वर्चस्ववाद की महिमा को स्थापित करने में लगे हैं। उनका यही बर्ताव पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान के परिप्रेक्ष्य में रहा था। परमाणु शक्ति संपन्न पश्चिमी देशों को आशंका है कि ईरान परमाणु बम बना लेने के निकट है। यही आशंका इजरायल की है। हालांकि अभी तक इजरायल घोषित रूप में परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं है, लेकिन अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों का उसके सिर पर वरदहस्त है। अतएव इजरायल अपनी संपूर्ण शक्ति से ईरान पर हमला कर रहा है। ईरान के परमाणु केंद्र नतांज पर भी हमला बोल दिया है। कई ईरानी वैज्ञानिक भी हताहत हो चुके हैं। ट्रंप धमकी के लहजे में कह रहे हैं कि हम इस जंग का समापन 'असली अंत' के रूप में देखना चाहते हैं, जो केवल संघर्ष विराम में नहीं है। यह असली अंत ईरान को परमाणु समझौते के लिए बाध्य करने के साथ परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने में निहित लग रहा है। या फिर ईरान के 86 वर्षीय सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को सत्ता के शीर्ष पद से पदच्युत कर उन्हीं के वंश के किसी व्यक्ति को नेता बनाना है। इसी परिप्रेक्ष्य में यूएस ने दो लड़ाकू जहाज ईरान के निकट भेज दिए हैं। यूके ने भी इजरायल की मदद के लिए लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। फ्रांस भी ईरान की मदद करने को तत्पर है। साफ है ईरान के अस्तित्व पर चहुंओर से खतरा मंडरा रहा है।

ट्रंप 2018 में उस ऐतिहासिक परमाणु समझौते से अलग हो गए थे, जिसे बराक ओबामा ने अंजाम तक पहुंचाया था। हालांकि यह संभावना ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही बन गई थी। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान इस समझौते का खूब मखौल भी उड़ाया था। ट्रंप को हमेशा यह संदेह बना रहा है कि ईरान समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। यह आशंका इसलिए पुख्ता दिखाई दे रही थी, क्योंकि ईरान लगातार गैर परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा था। वर्तमान के युद्ध में ईरान इन्हीं मिसाइलों से इजरायल की राजधानी तेल अवीव और अन्य नगरों में भीषण हमले कर रहा है, इससे इजरायल को भारी नुकसान हुआ है। उस समय ओबामा ने ट्रंप के निर्णय को बड़ी भूल बताया था। दरअसल ओबामा को भरोसा था कि समझौते के बाद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम में कटौती की थी, लेकिन ट्रंप अंध-राष्ट्रवाद और अमेरिकी वर्चस्व को लेकर इतने पूर्वाग्रही हैं कि उन्हें न तो अमेरिकी विदेश नीति की फिक्र है और न ही विश्व शांति के प्रति उनकी कोई प्रतिबद्धता दिखाई देती है। इसीलिए यह आशंका जताई जा रही है कि ईरान ट्रंप के दबाव में नहीं आता है तो विश्व शक्तियों के संतुलन बिगड़ सकता है?

ईरान पर लगे प्रतिबंध हटने के साथ ही विश्व स्तरीय कूटनीति में नए दौर की शुरूआत होने लगी थी। ईरान, अमेरिका, यूरोपीय संघ और छह बड़ी परमाणु शक्तियों के बीच हुए समझौते ने एक नया अध्याय खोला था। इसे 'संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना' नाम दिया गया था। इसकी शर्तों के पालन में ईरान ने अपना विवादित परमाणु कार्यक्रम बंद करने की घोषणा की थी। बदले में इन देशों ने ईरान पर लगाए गए व्यावसायिक प्रतिबंध हटाने का विश्वास जताया था। प्रतिबंधों के बाद से ईरान अलग-थलग पड़ गया था। इसी दौर में ईरान और इराक के बीच युद्ध भी चला, जिससे वह बर्बाद होता चला गया। यही वह दौर रहा जब ईरान में कट्टरपंथी नेतृत्व में उभार आया और उसने परमाणु हथियार निर्माण की मुहिम शुरू कर दी थी। हालांकि ईरान इस मुहिम को असैन्य ऊर्जा व स्वास्थ्य जरूरतों की पूर्ति के लिए जरूरी बताता रहा था, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया गया। प्रतिबंध लगाने वाले राष्ट्रों के पर्यवेक्षक समय-समय पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम का निरीक्षण करते रहे थे, लेकिन उन्हें वहां संदिग्ध स्थिति का कभी सामना नहीं करना पड़ा। अंत में आशंकाओं से भरे इस अध्याय का पटाक्षेप तब हुआ जब अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने निगरानी के बाद यह कहा कि ईरान ऐसे किसी परमाणु कार्यक्रम का विकास नहीं कर रहा है, जिससे दुनिया का विनाश संभव हो। ओबामा ने इस समझौते में अहम् भूमिका निभाई थी। किंतु ट्रंप को पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद लगा कि इस समझौते में अमेरिका कुछ ज्यादा झुका है। बावजूद उसके कोई हित नहीं सध रहे हैं। ट्रंप की मंशा थी कि ईरान प्रतिबंधों से पूरी तरह बर्बाद हो जाए और अमेरिका के आगे घुटने टेक दे। लेकिन ऐसे परिणाम नहीं निकले। पश्चिमी एशियाई की राजनीति में ईरान की तात्कालिक हसन रूहानी सरकार का वर्चस्व कायम रहा। उसने रूस, चीन और भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाए, जो ट्रंप को कभी रास नहीं आए। ट्रंप की वजह से ही कोरिया प्रायद्वीप में अमेरिका की जग हंसाई हुई। दरअसल अमेरिका अपनी शक्ति की नींव पर ही कोई संधि करने का आदि रहा है। साफ है कि अमेरिका ईरान से करार तोड़कर ऐसे प्रतिबंधों की मंशा पाले था कि ईरान उसकी ताकत के आगे नतमस्तक तो हो ही और यदि भविष्य में समझौता हो तो पूरी तरह एकपक्षीय हो। यह निर्णय इस्लाम और ईसाईयत में टकराव का कारण भी बन सकता है।

इस समझौते की प्रमुख शर्तें थी कि अब ईरान 300 किलोग्राम से ज्यादा यूरेनियम अपने पास नहीं रख सकेगा। ईरान अपनी परमाणु सेन्ट्रीफ्यूज प्रयोगशालाओं में दो तिहाई यूरेनियम का 3.67 फीसदी भाग ही रख सकेगा। यह शर्त इसलिए लगाई गई थी, जिससे ईरान परमाणु बम नहीं बना पाए। दरअसल यूरेनियम की प्राकृतिक अवस्था में 20 से 27 प्रतिशत ऐसे बदलाव करने होते हैं, जो यूरेनियम को खतरनाक परमाणु हथियार में तब्दील कर देते हैं। ईरान ने यूरेनियम में परिवर्तन की यह तकनीक बहुत पहले हासिल कर ली थी। इस शंका के चलते उसे न्यूनतम मात्रा में यूरेनियम रखने की अनुमति समझौते में दी गई थी, जिससे वह आसानी से परमाणु बम नहीं बना पाए। सबसे अहम् पर्तों में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को परमाणु सेन्ट्रीफ्यूज के भंडार, यूरेनियम खनन एवं उत्पादन की निगरानी का भी अधिकार दे दिया गया था। यह शर्त तोड़ने पर ईरान पर 65 दिनों के भीतर फिर से प्रतिबंध लगाने की शर्त भी प्रारूप में दर्ज की गई थी। ईरान को उसे मिसाइल खरीदने की भी छूट नहीं दी गई थी। ईरान के सैन्य ठिकाने भी संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में थे। साफ है ईरान ने आर्थिक बदहाली के चलते इन शर्तों को मानने को बाध्य हुआ था। प्रतिबंध की शर्तों से मुक्त होने के बाद ईरान तेल और गैस बेचने लग गया था। भारत ने भी ईरान से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया था। भारत के लिए ईरान से तेल खरीदना इसलिए लाभदायी रहता है, क्योंकि भारत के तेल शोधक संयंत्र ईरान से आयातित कच्चे तेल को परिशोधित करने के लिहाज से ही तैयार किए गए हैं। गोया, ईरान के तेल की गुणवत्ता श्रेष्ठ नहीं होने के बावजूद भारत के लिए यह लाभदायी रहता है। भारत ईरान से रुपए में तेल खरीदता है, इसलिए यह तेल डॉलर या पौंड में खरीदे जाने की तुलना में सस्ता पड़ता है।

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि इजरायल ईरान पर जब तक परमाणु हमले बंद नहीं करता है तब तक परमाणु वार्ता स्थगित रहेगी। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में उस पक्ष से बातचीत व्यर्थ है, जो आक्रमणकारी का सबसे बड़ा समर्थक है। दूसरी तरफ ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजरायल को मदद करते हैं तो वह इन देशों के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। दरअसल अमेरिका के पश्चिम एशिया क्षेत्र के ईराक में विशेष खलों के बड़े शिविरों के अड्डे हैं। खाड़ी में अनेक सैन्य अड्डे हैं। ईरान के समर्थक सशस्त्र आतंकी गुट हमास और हिजबुल्ला भले ही कमजोर हो गए हों, लेकिन ईराक में इनके समर्थक मिलिशिया अभी भी मजबूत है। अमेरिका को ऐसी आशंका पूर्व में ही हो गई थी, इसलिए उसने अनेक सुरक्षाचलों को वापिस बुला लिया है। बहरहाल मध्यपूर्व में बढ़ता यह तनाव कहां पहुंचेगा फिलहाल कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि जो अमेरिका खुद के वर्चस्व के लिए युद्ध की जमीन को रक्त से सींच रहा है, अमेरिका बड़बोले ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद न तो रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोक सका है और न ही इजरायल और फिलिपींस के बीच युद्ध विराम कर पाया है। लिहाजा ट्रंप का यह अहंकार अस्थिर होती दुनिया में वैश्विक संघर्ष को बढ़ावा देने का काम कर रहा है

जोरों पर नकली खाद बीज का करोबार

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। किसी भी फसल की गुणवत्ता के लिए अच्छे खाद बीज की आवश्यकता होती है। यदि खाद बीज नकली या घटिया स्तर का प्रयोग में लाया जाए तो फसल का उत्पादन तो घटेगा ही साथ ही उसकी गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। इसलिए बाजार से बीज खरीदते समय अच्छे बीज का चयन करना बेहद जरूरी हो जाता है। किसान फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए उन्नत किस्म के बीज एवं खाद बाजार से खरीदते हैं, लेकिन किसान कई बार भ्रमक विज्ञापन या सूचनाओं के आधार पर खाद एवं बीज खरीद लेते हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ खेल नरसिंहपुर जिला में चल रहा है।

यदि ईमानदारी से जांच हो जाए तो यहां के कई व्यापारियों एवं दुकानदारों के पास खाद बीज एवं उर्वरक नकली पाए जा सकते हैं। उल्लेखनीय हैं कि बरसात का मौसम शुरू होने के पूर्व से शहरों से लेकर ग्रामीण अंचलों तक इन दिनों नकली दवा खाद, बीज बेचने का सिलसिला शुरु हो जाता है। किसानों को भ्रमित कर घटिया नकली नाम के खाद बीज दवा देकर रुपये कमाने का धंधा इन दिनों जोरों पर होता है। कृषि विभाग के अधिकारी मौन होकर संरक्षण देते नजर आते हैं। इसके चलते किसानों को घर बैठे खाद बीज पहुंचने के बहाने नकली सामान देने का धंधा जोरों पर है। कृषि विभाग की तरफ से कर्मचारियों के माध्यम से किसानों को सहकरी समितियों से ही खाद बीज, दवा खरीदने की सलाह भी नहीं दी जा रहीं है। किसानों को भ्रमित कर कुछ दलाल फर्जी नामों के खाद, बीज, दवा के पैकिट बेच जाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस पर विशेष

योग से चेतना, संगीत से समरसता

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

21 जून, सिर्फ एक तारीख़ नहीं, बल्कि आत्म-साक्षात्कार और वैश्विक सामंजस्य का एक पर्व है। यह दिन दो शक्तिशाली माध्यमों को समर्पित है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस। योग, जो हमें अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़ता है, और संगीत, जो हमें पूरे ब्रह्मांड से। आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोबायोलॉजी अब प्रमाणित करते हैं कि संगीत और योग दोनों मिलकर अवसाद, चिंता, उच्च रक्तचाप और नकारात्मक विचारों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इनका संयोजन हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली युगल है।

योगः सिर्फ व्यायाम नहीं, एक जीवनशैली क्रांति

योग कोई क्षणिक फ़ैशन नहीं है; यह भारत की हज़ारों वर्षों पुरानी आध्यात्मिक विरासत है। यह केवल शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि मन को शांत, आत्मा को मुक्त और जीवन को व्यवस्थित करने की एक संपूर्ण प्रणाली है। 21 जून को जब पूरी दुनिया सूर्य की ऊर्जा से सराबोर होती है, उसी समय हम योग के माध्यम से अपने भीतर के सूर्य को जागृत करने का संकल्प लेते हैं।

मैं स्वयं हर दिन योग का न केवल अभ्यास करता हूँ, बल्कि अपने अनुभव के आधार पर दूसरों को भी प्रेरित करता हूँ। योग ने मेरे जीवन में आत्म-नियंत्रण, स्पष्टता और मानसिक स्थिरता लाने में अमूल्य योगदान दिया है। मेरे लिए योग मात्र आसनों का अभ्यास नहीं, बल्कि एक समग्र जीवन शैली है।

आज से करें शुरुआत

याद रखें, "शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा दिन आज है।" आज ही से छोटे-छोटे क़दमों से शुरुआत करें। हर दिन 15 मिनट प्राणायाम और 15 मिनट सूर्य नमस्कार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएँ। सप्ताह में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स लें और उस समय का उपयोग योग निद्रा या ध्यान में करें। महीने में एक बार परिवार या टीम के साथ सामूहिक योग सत्र आयोजित करें। अपने गाँव, मोहल्ले या सोशल मीडिया पर #YogaForLife अभियान चलाकर दूसरों को भी प्रेरित करें।

योग और संगीतः एक वैज्ञानिक सामंजस्य

योग और संगीत, दोनों ही हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हैं और विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। जब आप योग और ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो यह न्यूरोप्लास्टिसिटी एकाग्रता की क्षमता को बढ़ाती है और भावनात्मक नियंत्रण में सुधार करती है। इसी तरह, संगीत सुनना आपके शरीर में 'हैप्पी हार्मोन्स' जैसे डोपामिन और ऑक्सीटोसिन के स्राव को बढ़ावा देता है, जिससे अवसाद और चिंता जैसी समस्याओं में कमी आती है। ये दोनों अभ्यास मिलकर आपके न्यूरो ट्रांसमीटर को संतुलित करते हैं, जिससे तनाव कम होता है और आप अधिक शांति और संतुष्टि महसूस करते हैं।

योग और संगीत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाएं

योग और संगीत को अपनी दिनचर्या में शामिल करना बेहद सरल और प्रभावी है। सुबह की शुरुआत 10 मिनट के ध्यान और 15 मिनट के योगासन से करें, जो आपके दिन को ऊर्जावान बनाएगा। दोपहर में, जब भी आपको थोड़ा ब्रेक मिले, शांत और मधुर वाद्य संगीत सुनें। यह आपको तरोताजा महसूस कराएगा और काम पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। शाम को, 5 मिनट की गहरी श्वास के साथ रिलैक्सिंग संगीत सुनें। यह दिनभर की थकान को दूर करने और तनाव को कम करने में सहायक होगा। रात को सोने से पहले योग निद्रा या गाइडेड संगीत ध्यान का अभ्यास करें, जिससे आपको गहरी और आरामदायक नींद आएगी। यह सरल संयोजन आपको एक स्वस्थ, संतुलित और आनंदमय जीवन जीने में मदद कर सकता है।

संगीतः वह शक्ति जो शब्दों से परे है

संगीत वह भाषा है जो दिलों को जोड़ती है, सीमाओं को तोड़ती है और आत्मा को छूती है। जहाँ योग आपको आत्म-केंद्रित करता है, वहीं संगीत आपको सामूहिक चेतना से जोड़ता है।

नव निर्माण की ओर एक कदम

आज का दिन केवल उत्सव का नहीं, बल्कि एक नए, संतुलित जीवन की शुरुआत का अवसर है। योग और संगीत को एक साथ अपनाकर हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहाँ तन, मन और आत्मा– तीनों संतुलन में हों। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप योग को अपने जीवन में उतारें, इसे अपने परिवार में फैलाएँ और समाज में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाएँ। साथ ही, संगीत को सिर्फ मनोरंजन न समझें– इसे जीवन के उत्सव का अभिन्न हिस्सा बनाएँ। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ!

चिंता का विषय

जलाशयों का घटता स्तर

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

आज जलाशयों की कमी हमारे देश सहित पूरी दुनिया में एक बड़ी समस्या बन गई है। जलाशय पेयजल का मुख्य स्रोत हैं, लेकिन उद्योग, कृषि, बिजली उत्पादन और पारिस्थितिक संतुलन में भी महत्वपूर्ण हैं। अधिकांश जलाशयों में जलस्तर पिछले कुछ वर्षों में तेजी से गिर रहा है, जो जलवायु परिवर्तन, मानसून के असंतुलन और लगातार सूखे से हुआ है। इसका प्रभाव न केवल मनुष्यों पर बल्कि जीव-जंतुओं और पर्यावरण पर भी है। भारत में जारी पानी की रिपोर्ट कार्ड के अनुसार देश के 161 जलाशयों में केवल 42 प्रतिशत ही पानी शेष हैं और आगे लगातार घट रहा है। गिरने वाले जल स्तर के कई कारण हो सकते हैं उनमें जल दोहन का अतिरेक सबसे बड़ा कारण है। खेती में अधिक पानी वाली फसलों का उत्पादन, खासकर पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, भूजल को तेजी से कम कर रहा है। इसके अलावा, औद्योगिकीकरण, बढ़ती आबादी और शहरीकरण ने जल स्रोतों पर दबाव बढ़ा दिया है। वन क्षेत्रों की कटाई और कंक्रीट के जंगलों ने जलग्रहण क्षेत्रों को नष्ट कर दिया है, जिससे बारिश का पानी जमीन में नहीं जा पाता और जलाशयों को भर नहीं पाता। हर वर्ष बढ़ता तापमान भी वजह है। बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं जिससे जल का भंडार ही कम नहीं हो रहा है बल्कि तेजी से पानी बहने से वर्षा भी बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। भारत में मॉनसून की अनियमितता से जलाशयों में जल स्तर में गिरावट आ सकती है। इस संकट से पूरा समाज प्रभावित होता है। किसानों को फसलों के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलता, जिससे उत्पादन कम होता है और आर्थिक हालात खराब होते हैं। देश में सिर्फ 45 प्रतिशत कृषि भूमि ही सिंचित है जो कि मुख्यतः भुजल पर निर्भर हैं। हमारे देश की कुल 143 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का लगभग 55 प्रतिशत वर्षाधारित है तथा बारानी खेती के अंतर्गत आता है। देश में लगभग 95 प्रतिशत ज्वार व बाजरा तथा 90 प्रतिशत मोटे अनाजों का उत्पादन वर्षा आधारित क्षेत्रों से ही आता है। इसके अलावा 91 प्रतिशत दालों और 85 प्रतिशत तिलहनों की पैदावार भी बारानी क्षेत्रों में होती है

शहरों में अनियमित जल वितरण से गरीब वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होता है। वहीं, जलविद्युत परियोजनाओं में उत्पादित बिजली की मात्रा भी घट जाती है, जिससे ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है। जलाशयों का सूखना स्थानीय पारिस्थितिकी पर असर डालता है। जैसे-जैसे मछलियों की प्रजातियाँ विलुप्त होने लगती हैं, इससे पक्षियों का प्रवास प्रभावित होता है। जलाशयों का जल जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है और जल स्तर में गिरावट से पारिस्थितिकी क्षति हो सकती है।

इस खराब स्थिति से निपटने के लिए सब लोग मिलकर काम करना चाहिए। पहले, बारिश का पानी भूजल के रूप में सुरक्षित रखने के लिए वर्षा जल संचयन अनिवार्य होना चाहिए। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी आधुनिक जल संरक्षण तकनीक का प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। किसानों को समय समय पर कृषि रसायनों व रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के लिए उचित परामर्श देकर भी भुजल पर इनके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। इसके लिए किसानों को उर्वरकों की उपयुक्त प्रयोग विधि व उनके प्रयोग करने के उचित समय की जानकारी देना अति आवश्यक है। इस प्रकार प्रयोग किए गए उर्वरकों का पूरा पूरा फायदा फसल को मिलेगा। साथ ही भुजल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। जल बचत के लिए आम लोगों को शिक्षित और प्रेरित करना चाहिए। साथ ही, सरकार को जल प्रबंधन के कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। भूजल की बर्बादी को लेकर सख्त कायदे कानून बनाए जाने चाहिए। इस संबंध में जन जागरूकता बहुत जरूरी है। लोगों को बताना होगा कि भूजल की एक बूंद को मृदा सतह पर पहुंचाने में वैज्ञानिकों व किसानों को कितना पसीना बहाना पड़ता है। यदि आज हम इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाते, तो आने वाली पीढ़ियाँ जल संकट का सामना करनी पड़ेगी।

योग दिवस 2025 पर विदिशा पुलिस का संकल्पः स्वस्थ पुलिस, सशक्त समाज

-कैलाशचंद्र जैन

जगत प्रवाह. विदिशा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर पुलिस लाइन विदिशा में भव्य सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण तथा सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अंशुल गुप्ता, विधायक मुकेश टंडन, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सीईओ की गरिमामयी उपस्थिति रही। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे, रक्षित निरीक्षक भूर सिंह चौहान सहित पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पूरे समर्पण के साथ योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में अन्य जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी- कर्मचारी व स्कूली छात्र-छात्राओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लेकर योग के महत्व को आत्मसात किया। योग प्रशिक्षकों द्वारा सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ध्यान व अन्य योगासन कराए गए। यह आयोजन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के साथ-साथ सामूहिक अनुशासन और ऊर्जा का प्रतीक बना। विदिशा पुलिस द्वारा किया गया यह आयोजन योग के सामाजिक महत्व और स्वस्थ जीवनशैली की दिशा में जागरूकता फैलाने का एक प्रेरक प्रयास रहा।

एम्स भोपाल ने "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग" थीम के साथ 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया

-समता पाठक

जगत प्रवाह. भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के नेतृत्व में संस्थान ने समग्र स्वास्थ्य और निवारक देखभाल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) का उत्साहपूर्वक आयोजन किया। यह कार्यक्रम एम्स भोपाल के आयुष विभाग द्वारा आयोजित किया गया, जो सुबह 6:30 बजे आईपीडी भवन स्थित गांधी गैलरी में प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर फैकल्टी, छात्र-छात्राओं, स्टाफ सदस्यों एवं आम नागरिकों ने सक्रिय सहभागिता की। इस वर्ष की थीम "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग" के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि व्यक्ति का स्वास्थ्य, पर्यावरणीय संतुलन और वैश्विक सामंजस्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में सभी प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम किए, जिससे कार्यक्रम स्थल पर एक शांत, अनुशासित और सकारात्मक वातावरण निर्मित हुआ। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री निखिल गजराज विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। डॉ. सुनील मलिक (माननीय अध्यक्ष, एम्स भोपाल) इस कार्यक्रम में संरक्षक के रूप में उपस्थित रहे। प्रो. (डॉ.) अजय सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में प्रो. (डॉ.) रजनीश जोशी, डीन (शैक्षणिक); मयंक कपूर, प्रभारी उप निदेशक (प्रशासन) और डॉ. मयंक दीक्षित (प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक) उपस्थित रहे।

कानून-व्यवस्था की स्थिति के संबंध में तत्काल कार्रवाई का अनुरोध

-अमित राय

जगत प्रवाह. कोलकाता। पश्चिम बंगाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, सांसद बालूरघाट लोकसभा व केन्द्रीय राज्यमंत्री शिक्षा एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, डॉ. सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पश्चिम बंगाल में गंभीर कानून और व्यवस्था की स्थिति के संबंध में पत्र लिखा है और तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया है। पत्र में लिखा है कि मैं आपका ध्यान पश्चिम बंगाल, विशेष रूप से डायमंड हार्बर क्षेत्र में अत्यधिक चिंताजनक और बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूं। जहां निर्वाचित प्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर लगातार राजनीतिक हिंसा की जा रही है। 19 जून 2025 को, जब मैं पिछले हमलों के पीड़ितों से मिलने और जमीनी हालात का आंकलन करने के लिए डायमंड हार्बर की आधिकारिक यात्रा पर गया था, तो मेरे काफिले पर एक हिंसक भीड़ ने हमला किया, जिसमें कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कार्यकर्ता शामिल थे। पत्थर फेंके गए, वाहनों में तोड़फोड़ की गई और मेरे साथ आए कई लोग घायल हो गए। इस हमले से मेरी और मेरे साथियों की जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया। आगे उन्होंने लिखा कि विशेष चिंता की बात यह है कि वरिष्ठ जिला अधिकारियों की पूरी तरह से निष्क्रियता रही। पुलिस अधीक्षक राहुल गोस्वामी, घटनास्थल पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई निवारक या सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए। अमलान कुसुम घोष, आईपीएस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) मेरे निर्धारित दौरे की पूर्व जानकारी होने के बावजूद घटनास्थल पर रिपोर्ट नहीं किए। स्थिति को अंततः सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मियों की त्वरित प्रतिक्रिया के कारण ही नियंत्रित किया जा सका, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई मेरी जैड सुरक्षा का हिस्सा है। यह न केवल कानून और व्यवस्था का पतन है, बल्कि एक केंद्रीय मंत्री और सांसद की गरिमा और सुरक्षा पर भी सीधा हमला है। परिणामस्वरूप, मैंने लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 222 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का नोटिस प्रस्तुत किया है, जिसमें इस गंभीर मामले पर उचित कार्रवाई की मांग की गई है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)*